



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2019/वैशाख 12, 1941
No. 134]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2019/VAISAKHA 12, 1941

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2019

राज्य एवं केंद्र द्वारा लागू करें और लेवियों में छूट प्रदान करने के लिए योजना (आरओएससीटीएल)

फा. सं. 14/26/2016-आईटी (खंड II) (भाग-II)—परिधानों और मेडअप्स पर राज्य एवं केंद्र द्वारा लागू करें और लेवियों में छूट प्रदान करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 07.03.2019 की अधिसूचना के तहत परिधानों और मेडअप्स के निर्यात पर राज्य एवं केंद्र द्वारा लागू करें और लेवियों में छूट प्रदान करने के लिए योजना अधिसूचित की है।

2. उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम में छूट की प्रकृति, स्क्रिप जारी करने का तंत्र, गलत घोषणा पर आधारित दावा/अधिक दावा और आरओएससीटीएल के अंतर्गत वसूली की प्रक्रिया को एतद्वारा निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:

(क) छूट की प्रकृति

राज्य एवं केंद्र द्वारा लागू करें और लेवियों में छूट प्रदान करने की योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी किए जाएंगे। स्क्रिप और उनके आधार पर आयातित/स्वदेशी तौर पर खरीदी गई वस्तुएं स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होंगी। स्क्रिप का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:

(i) परिशिष्ट एफटीपी 2015-2020 के 3ए में सूचीबद्ध मदों को छोड़कर डीओआर की अधिसूचना के अनुसार पूंजीगत वस्तुओं सहित इनपुटों अथवा वस्तुओं के आयात के लिए उत्पाद शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3 (1), 3(3) और 3(5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राथमिक सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान।

(ii) इनपुटों अथवा वस्तुओं की स्वदेशी खरीद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान।

(ख) आरओएससीटीएल के अंतर्गत स्क्रिप जारी करने की व्यवस्था

(i) विदेश व्यापार महानिदेशक इस प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा जिसके अंतर्गत निर्यातक इस योजना के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं और राजस्व विभाग स्क्रिप का उपयोग करने की क्रियाविधि को अधिसूचित करेगा।

(ii) शिपिंग बिल फाइल करते समय निर्यातक को आरओएससीटीएल के लिए उपयुक्त योजना कोड की घोषणा करते हुए योजना की शर्तों और निबन्धनों की स्वीकृति में छूट का दावा करके आरओएससीटीएल योजना के विकल्प का चयन विवेक सम्मत तरीके से करना होता है। ऐसे शिपिंग बिल फाइल करना निर्यातक की स्व-घोषणा होगी कि वह दर और छूट के लिए उतना पात्र है जितना निर्यातक ने दावा भी किया है और वह उन विशिष्ट करों के क्रेडिट/छूट/रिफंड/प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा जिसमें किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य लेवियों और केंद्रीय लेवियों की छूट शामिल है।

(ग) गलत घोषणा पर आधारित दावा/अधिक दावा वसूली की प्रक्रिया

(i) बिक्री से प्राप्त राशि के आधार पर छूट दी जाती है जिसकी अनुमति विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत निर्धारित समय के अंदर दी जाती है और जिसका पालन न किए जाने पर यह माना जाएगा कि छूट नहीं दी गई है। आरओएससीटीएल के तहत गलती से या अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी एफटी (डीएंडआर) अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा गलत गणना से स्क्रिप के माध्यम से जारी की गई छूट की अधिक भुगतान की राशि को निर्यातक द्वारा वापस करना अपेक्षित है। पुनर्भुगतान, वसूली या राशि की वापसी की स्थिति में यदि न्याय निर्णय आदेश के तहत कोई दंड लगाया गया हो तो निर्यातक द्वारा ऐसे दंड के साथ स्क्रिप से डेबिट की तारीख से पुनर्भुगतान, वसूली या राशि वापसी की तारीख तक पंद्रह प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा। आरओएससीटीएल के तहत अप्रयुक्त स्क्रिप को ब्याज के बिना सरेंडर किया जाएगा। तथापि, गलत घोषणा करने और धोखाधड़ी पूर्ण प्रक्रिया अपनाने के मामले में एफटी (डीएंडआर) अधिनियम के उपबंधों के तहत दंड लगाया जा सकता है।

(ii) यदि वसूली देय है, तो डीजीएफटी या डीजीएफटी द्वारा पदनामित कोई अधिकारी निर्यातक को पत्र जारी करेगा और निर्यातक से अनुरोध करेगा कि वह सीमा शुल्क के संगत खाता शीर्ष में 30 दिन के अंदर पूरी राशि (मूलधन और ब्याज) जमा करे। यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो एफटी (डीएंडआर) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और ब्याज सहित शुल्क की वसूली के लिए उचित कार्रवाई के साथ-साथ दंड भी लगाया जा सकता है।

(घ) इसके पश्चात, योजना से संबंधित शेष मुद्दों पर अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसका निर्णय बाध्यकारी होगा।

(ङ) वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 8.3.2019 की अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी(खंड-II) के अंतर्गत अनुसूचियों में निर्दिष्ट आरओएससीटीएल की दरें उस वस्तु अथवा उत्पाद के निर्यात के लिए लागू नहीं होंगी यदि -

i. ऐसी वस्तु अथवा उत्पाद का निर्माण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के अंतर्गत आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वेयरहाउस में किया गया है;

ii. ऐसी वस्तु अथवा उत्पाद का निर्माण अथवा निर्यात अग्रिम प्राधिकार अथवा समुचित विदेश व्यापार नीति की शुल्क छूट योजना के अंतर्गत जारी शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार के प्रति निर्यात दायित्व के अंतर्गत किया जाता है;

यह भी प्रावधान है कि यदि दिनांक 13.08.2016 की अधिसूचना संख्या 45/2016-सीमा शुल्क से संबंधित निर्यात दायित्व के अंतर्गत विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.04ए के अंतर्गत जारी विशेष अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत निर्यात किया जाता है, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट आरओएससीटीएल की दरें लागू होंगी।

- iii. ऐसी वस्तु अथवा उत्पाद का निर्माण अथवा निर्यात समुचित विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अंतर्गत शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई के रूप में लाइसेंसशुदा इकाई द्वारा किया जाता है;
- iv. ऐसी वस्तु अथवा उत्पाद का निर्माण अथवा निर्यात मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इन्हीं इकाइयों द्वारा किया जाता है;
- v. ऐसी वस्तु अथवा उत्पाद का निर्माण अथवा निर्यात दिनांक 01 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 32/1997-सीमा शुल्क का लाभ प्राप्त करके किया जा रहा है।

अदिति दास राउत, व्यापार सलाहकार

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2019

Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL)

F.No.14/26/2016-IT(Vol.II)(Part II).—In pursuance of the decision of the Government of India to rebate all embedded State and Central Taxes and Levies on garments and made-ups, the Ministry of Textiles has notified the scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) on export of garments and made-ups vide notification dated 07.03.2019.

2. In continuation of the aforesaid notification, nature of rebate, mechanism of issue of scrips, over-claim/ claim based on mis-declaration and procedure for recovery under RoSCTL are hereby notified as follows:-

(a) Nature of Rebate

Scrips shall be granted under the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies. The Scrips and goods imported/ domestically procured against them shall be freely transferable. The Scrips can be used for:

- (i) Payment of Basic Customs Duty and Additional Customs Duty specified under sections 3 (1), 3 (3) and 3 (5) of the Customs Tariff Act, 1975 for import of inputs or goods, including capital goods, as per DoR Notification, except items listed in Appendix 3A of FTP 2015-2020.
- (ii) Payment of Central excise duties on domestic procurement of inputs or goods.

(b) Mechanism of Issue of Scrips under the RoSCTL

- (i) The Director General of Foreign Trade will notify the procedure under which exporters can apply for the rebate under the scheme, and the Department of Revenue will notify the procedure for utilization of the scrips.
- (ii) An exporter has to make a conscious choice to opt for ROSCTL scheme by making claim for rebate in acceptance of the scheme's terms and conditions while declaring the relevant scheme code for RoSCTL at the time of filing of the shipping bills. Such filing of shipping bills would be the exporter's self-declaration that he is eligible for the rate and rebate in as much as exporter has not claimed and shall not claim the credit/ rebate/ refund/ reimbursement of the specific taxes that comprise the rebate of State levies and Central Levies under any other mechanism.

(c) Over-claim/ claim based on mis-declaration and procedure for recovery

- (i) The rebate allowed is subject to the receipt of sale proceeds within time allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 failing which such rebate shall be deemed never to have been allowed. Action under the FT (D&R) Act may be taken by the Regional Authorities for recovery of erroneous or excess paid RoSCTL. Further, the exporter is required to return any over-payment of rebate issued through the scrips arising from miscalculation. Where there is repayment, recovery or return, interest shall also be paid by the exporter at the rate of fifteen per cent per annum calculated from the date of debit of the scrip till the date of repayment, recovery or return along with penalty, if imposed under an Adjudication order. Unutilized scrip under RoSCTL would be

surrendered with no interest, however, a penalty may be imposed in case of mis-declaration and fraudulent practice under the provisions of FT(D&R) Act.

- (ii) In case a recovery is due, DGFT or any officer designated by the DGFT shall issue a letter to the exporter and request the exporter to deposit the full sum (principal plus interest) within 30 days in the relevant account head of Customs. In case of non-compliance, action under the FT(D&R) Act would be initiated and a penalty might be imposed along with suitable action to recover duty plus interest.
- (d) Residual issues related to the Scheme arising subsequently shall be considered by the Inter Ministerial Committee, whose decisions would be binding.
- (e) **The rates of RoSCTL specified in the Schedules under Ministry of Textiles Notification No. 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 8.3.2019 shall not be applicable to export of a commodity or product if such commodity or product is –**
 - (i) Manufactured partly or wholly in a warehouse under section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
 - (ii) Manufactured or exported in discharge of export obligation against an Advance Authorisation or Duty Free Import Authorisation issued under the Duty Exemption Scheme of the relevant Foreign Trade Policy:

Provided that where exports are made against Special Advance Authorisation issued under Paragraph 4.04A of the Foreign Trade Policy 2015-20 in discharge of export obligations in terms of Notification No. 45/2016-Customs, dated 13th August, 2016, the rates of RoSCTL specified in the said Schedule shall apply.
 - (iii) Manufactured or exported by a unit licensed as hundred per cent Export Oriented Unit in terms of the provisions of the relevant Foreign Trade Policy;
 - (iv) Manufactured or exported by any of the units situated in Free Trade Zones or Export Processing Zones or Special Economic Zones;
 - (v) Manufactured or exported availing the benefit of the Notification No. 32/1997-Customs dated 1st April, 1997.

ADITI DAS ROUT, Trade Adviser